S.N.	Name of the project, location and company cooperative	Estimated capital cost (Rs. Crore)	Addl. Production envisaged		Zero date	Approved original date of commissioning	Remarks
			Product	Capacity (In Lakh MTPA)			
3.	Revamp of Namrup Plants of Hindustan Fertilizer Corporation Ltd., (HFC), Namrup, Assam.	350.00	Urea	3.28	2.11.98	1.5.2001	

Total Estimated Capital Cost : Rs. 2242.38 crore
Total Urea : 13.03 lakh MTPA

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

Manufacture of Methanol in India

1086. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what is the annual installed and actual average capacity of major manufacturers of Methanol in India during the recent years;

(b) whether these manufacturers have pleaded for increase in import duty on Methanol;

(c) if so, the details of the pleadings;

(d) whether Government have since acceded to the demand; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) Annual installed capacity of Methanol in the country is 3,86,000 MT. There are two major manufacturers of Methanol, namely M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers Co. Ltd. and M/s Deepak Fertilizers & Petrochemicals Corporation Ltd, with installed capacities of 1,20,000 and 1,00,000 MT/year respectively.

(b) Yes, Sir.

(c) to (e) The request for increase in import duty on Methanol has been made by the manufacturers on account of higher cost of indigenous production and fall in international prices.

However, at the same time, the Government has also received representations from consumers of Methanol pointing out that this constitutes a basic building block and therefore, its availability at cheaper prices should be ensured. In the Union Budget for 1999-2000, the basic customs duty on Methanol remains unchanged at 25%.

Liabilities in respect of Dexamethason

1087. SHRI MUNAVVAR HASAN: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what are the details of liabilities assessed in respect of Dexamethason against Merind and Cadila from April, 1979 till they implemented Government-fixed prices;

(b) whether liabilities against both the companies have not been fully assessed and they have been shown favouritism;

(c) what were the prices of bulk drugs adopted by them in the formulations at

the time of commencement of DPCO, 1979 and what was the price notified by Government for these drugs; and

(d) what steps have been taken to investigate the bungling?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) to (d) The DPEA liabilities against M/s Merind and Cadila in respect of bulk drug Dexamethasons and its formulations have been assessed, on tentative basis, for the entire period of DPCO, 1979 and the same has been communicated to both the companies. At present, both these cases are pending before the Drug Prices Liabilities Review Committee constituted by the Department to get the entire matter relating to the DPEA recoveries reviewed by it. Government can take further course of action only after receipt of the Reports of the said Committee in both the cases.

उर्वरक क्षेत्र के लिए ऋण

1088. श्री गोपाल सिंह चौलेकी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरक क्षेत्र के लिए ऋणों का प्रावधान इसकी आवश्यकता से कहीं कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान उर्वरक क्षेत्र में किए गए पूंजी निवेश का प्रतिशत क्या है;

(घ) इस क्षेत्र की आवश्यकता की तुलना में उक्त अवधि के दौरान वास्तव में कुल कितनी पूंजी उपलब्ध कराई गई;

(ङ) इस क्षेत्र में कम पूंजी निवेश किए जाने के क्या कारण हैं;

(च) इस स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(छ) 1999-2000 के दौरान इस क्षेत्र के लिए पूंजी की कुल अनुमानित आवश्यकता क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए०के० पटेल): (क) और (ख) उर्वरक परियोजनाएं शुरू करने तथा कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सम्पर्क करने की जिम्मेवारी उर्वरक उद्योग के प्रवर्तकों/उद्यमियों की है। जहां तक उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों का संबंध है, वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के दौरान बजटीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराये गये ऋण इस प्रकार हैं:—

(रुपये करोड़)

वर्ष	योजनागत	योजनाभिन्न	योग
1996-97	250.71	440.34	691.05
1997-98	191.38	406.49	597.87
1998-99 (संशोधित अनुमान)	180.88	400.00	580.88

(ग) से (छ) उर्वरक उद्योग अत्यधिक पूंजी निवेश वाला उद्योग है जिसकी स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उर्वरक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं:—

(i) नये संयंत्रों की स्थापना करने/मौजूदा संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए पूंजीगत मामलों के आयात पर सीमा शुल्क की रियायती दर।

(ii) उर्वरक कच्चे मालों तथा मध्यवर्तियों का रियायती दर पर आयात।

(iii) उर्वरक परियोजनाओं के पूंजीगत माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं की संभावित निर्यात लाभ बशर्ते ऐसी आपूर्तियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली पद्धति के तहत की जायें।

(iv) पोषकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों पर रियायत।

(v) वर्तमान में यूरिया पर लागू प्रतिधारण मूल्य सह-सब्सिडी स्कीम के तहत उद्यमियों को निवेश पर लाभ की मुनासिब दर।

(vi) मौजूदा उर्वरक संयंत्रों का रेट्रोफिटिंग/पुनरुद्धार।

(vii) नेफथा पर आधारित विस्तार परियोजनाओं की स्थापना करके तथा मौजदा संयंत्रों और कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में दोहरी